

राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा

वर्ष 15 अंक 1

जनवरी-जून 2013

1. "राधा कमल मुकर्जी एक भारतीय समाजशास्त्र की तलाश (Radhakamal Mukerjee and the Quest for an Indian Sociology)"—डॉ. मनीष के. ठाकुर, Associate Professor, Public Policy and Management Group, Indian Institute of Management Kolkata and is currently fellow, Indian Institute of Advanced Study, Shimla,

'सोशियोलॉजिकल बुलेटिन' के वर्ष 61 अंक 1 अप्रैल 2012 में छपे इस लेख को हिन्दी में अनुदित करके छापने के लिए हम इस आलेख के विद्वान लेखक डॉ. मनीष के. ठाकुर (आई.आई.एम. कोलकाता), अनुवाद एवं प्रकाशन अधिकार प्रदान करने के लिए उदारमना प्रोफेसर एन.जयराम (प्रबन्ध सम्पादक सोशियोलॉजिकल बुलेटिन) तथा भाषांतरण के चुनौतीपूर्ण कार्य को सम्पन्न करने के लिए अनुवादक डॉ. उमाचरण (वरिष्ठ प्रवक्ता समाजशास्त्र, बरेली कालेज, बरेली) तीनों के आभारी हैं। भारतीय समाज एवं संस्कृति के अध्ययन में प्रयुक्त पाश्चात्य समाज वैज्ञानिक उपागमों की राधाकमल मुकर्जी द्वारा की गयी आलोचना के मूल्यांकन पर आधारित इस शोध पत्र का उद्देश्य उनके कृतित्व के समालोचनात्मक एवं चुनिन्दा अध्ययन द्वारा एक वैकल्पिक देशज (भारतीय) दृष्टिकोण के तत्वों को पहचानना है। इसमें मुकर्जी के मूल सरोकारों एवं विश्लेषणात्मक विषय-वस्तु को प्रस्तुत करते हुए उनके पथ प्रदर्शक योगदान में पाश्चात्य आधुनिकता की आलोचना की रूपरेखा की गवेषणा की गयी है। इसका केन्द्र बिन्दु मुकर्जी द्वारा प्रस्तुत मनुष्य, समाज एवं संस्कृति के सम्बन्धों की संकल्पना द्वारा 'भारतीय' की व्याख्या की प्रकृति एवं आधार वाक्यों को भी रेखांकित करना है।

2. "गुणात्मक चिकित्सा समाजविज्ञान में साम्प्रतिक प्रवणता"—प्रोफेसर ए० एल० श्रीवास्तव, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (अवकाश प्राप्त) समाजशास्त्र एवं समाज सेवा विभाग, बी.एच.यू., वाराणसी (उ.प्र.), डॉ० अशोक कुमार श्रीवास्तव, शोध परियोजना निर्देशक सम्बद्ध हिन्दू पी. जी. कालेज जमानियां गाजीपुर (उ० प्र०)

स्वास्थ्य एवं रूग्णता का मुद्दा अन्तःक्रियात्मक कार्य का केन्द्र बिन्दु है जो रोगी एवं चिकित्सक के मध्य घटित होता है। इस प्रक्रिया में रोगी का परिवार नियोजन आदि का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। चिकित्सा समाज विज्ञान के क्षेत्र में समसामयिक स्थिति में गुणात्मक चिकित्सा को अतिशय महत्व प्रदान किया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं रोगी से संबंधित विविध प्रकार की समस्याओं का निदान केवल जैविक आधार पर न करके उसके बहुविध प्रकार के सामाजिक-सांस्कृतिक-मनोवैज्ञानिक आधारों पर करने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। प्रस्तुत आलेख गुणात्मक चिकित्सा की समसामयिक दशा तथा चिकित्सा संगठन की निदान प्रक्रिया के अंतर्गत इसके महत्वपूर्ण योगदान का विस्तृत विश्लेषण है।

3. "मानवाधिकार की अवधारणा : एक विवेचना"—डॉ. सुरेन्द्र बहादुर सिंह, संकाय प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष विधि संकाय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (उ.प्र.)

मानवाधिकार संसार के सर्वोत्कृष्ट प्राणी मानव को समाज में गरिमा तथा मानव के रूप में प्रस्थिति दिलाने के प्रबल संबल हैं। मानवाधिकार उन आत्यंतिक अधिकारों की अवधारणा है जिन्हें ईश्वर ने मानव को जन्म के साथ ही प्रदान किया है, इसलिए ये शाश्वत हैं और किसी भी देश के संविधान, राजनीतिक दल, शैक्षणिक व्यवस्था अथवा अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं से भी पुराने हैं। प्रस्तुत आलेख के अंतर्गत मानवाधिकार की अवधारणा की नीतिशास्त्रीय, उपयोगितावादी, न्यायिक, विधिशास्त्रीय, राजनीतिक, समाजशास्त्रीय एवं संवैधानिक आदि अनेकानेक दृष्टियों से विस्तृत व्याख्या की गई है।

4. "पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में स्त्री-शिक्षा के उन्नयन का तुलनात्मक अध्ययन-मूलभूत"—डॉ० बी. सी. शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, बी०एड० विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर, चमोली (उत्तराखण्ड), डॉ० गीता शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर, चमोली (उत्तराखण्ड)

सांप्रत भारत, शिक्षा को समाज व राष्ट्र के लिये संजीवनी मानता है। मानवीय संसाधनों के पूर्ण विकास, परिवार में सुधार, बच्चों के चरित्र निर्माण, देश के उत्थान आदि के लिये यहां बालिकाओं की शिक्षा, बालकों की शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। परन्तु भारत के लिये यह दुर्भाग्य का विषय है कि आज तक भी महिलाओं की शिक्षा का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। इसी तथ्य को प्रमाणित एवं प्रकाशित करने की दृष्टि से प्रस्तुत आलेख शिक्षा की मूलभूत एवं मैदानी क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के उन्नयन का तुलनात्मक अध्ययन करने का एक प्रयास कहा जा सकता है।

5. "भारत को चौतरफा घेरता चीन माध्यम बनते देश"—डॉ. वीरेन्द्र चावरे, प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

21वीं सदी में भारत और चीन एशिया की दो उभरती महाशक्तियां हैं। भारत से चीन के सीमा विवाद होने के बावजूद चीन ने भारत के साथ आर्थिक संबंध स्थापित कर रखे हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि आर्थिक संबंध ऊंचाई पर होने के बावजूद वह भारत को चौतरफा घेरने का हर संभव प्रयास क्यों कर रहा है? अपनी नौसेना हेतु अग्रिम आधार तैयार करने हेतु बंगाल की खाड़ी, हिन्द महासागर और अरब सागर के समुद्री रास्ते से भारत की सामुद्रिक घेराबंदी क्यों करना चाहता है? क्या वह पड़ोसी देशों से सैन्य व सामुद्रिक सुविधाएं अर्जित कर पूरे एशिया और हिन्द महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। प्रस्तुत आलेख के अंतर्गत इन प्रश्नों की न केवल तार्किक एवं तथ्यपरक समीक्षा की गई है अपितु भारत को अपने हितों को दृष्टिगत रखते हुए एक स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाने तथा दक्षिण एशियाई देशों के साथ-साथ पूर्वी एशियाई देशों के साथ भी आर्थिक व सामरिक संबंधों पर बल देने एवं अन्य सुझाव भी प्रस्तुत किये गये हैं।

6. "बाध्य एकल परिवारों के किशोरों में समाज-जनित आवश्यकता संतोष का अध्ययन"—डॉ० मधु नयाल, एसोसिएट प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग, एस.एस.जे. परिसर, कुमायूं विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

प्रस्तुत अध्ययन कुमायूं क्षेत्र के किशोरों पर समाज-जनित आवश्यकता संतोष का मापन करने हेतु किया गया है। इस हेतु बाध्य एकल परिवारों के क्रमशः 29 किशोरों का चयन बहुस्तरीय स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्शन विधि के प्रयोग द्वारा किया गया, जिनकी आयु 13 से 19 वर्ष थी। समाज-जनित आवश्यकता संतोष के मापन हेतु चौहान, धर एवं सिंह (1986) द्वारा निर्मित समाज-जनित आवश्यकता संतोष मापनी प्रशासित करवाई गई। दोनों समूहों में अन्तर के मापन हेतु टी-परीक्षण प्रयुक्त किया गया। प्राप्त परिणाम प्रदर्शित करते हैं कि बाध्य एकल परिवारों की किशोरियों की अपेक्षा किशोरों में नम्रता एवं नकारात्मक पक्ष का स्तर उच्च पाया। किन्तु समाज-जनित आवश्यकता संतोष के अन्य आयामों स्वीकृति, सहयोग, तादात्मीकरण, प्रभुत्व, सकारात्मक पक्ष, अस्वीकृति, पृथक्करण, विभेदीकरण, में .05 स्तर पर कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

7. "वाराणसी जनपद में गृह-त्याज्य का संकलन एवं निस्तारण : एक विश्लेषण"—डॉ० सुमन मिश्रा, अध्यक्ष गृह विज्ञान विभाग, श्री अग्रसेन कन्या पी.जी. कालेज, वाराणसी (उ.प्र.)

अति प्राचीन काल से ख्यातिनामा नगर वाराणसी का उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित विविध नगरों में आज भी पृथक सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व है। जीवनदायिनी माँ गंगा के किनारे बसे इस अतिशत पवित्र नगर की गणना अतुलनीय धार्मिक महत्व के कारण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में की जाती है। धार्मिक विशिष्टता के साथ-साथ औद्योगीकरण एवं नगरीकरण के परिणामस्वरूप इस नगर में विविध

प्रकार के वृहद् एवं लघु उद्योगों का भी प्रसार हुआ है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के साथ-साथ अनेकानेक शिक्षा संस्थानों की स्थापना के कारण शिक्षा का भी महत्वपूर्ण केन्द्र है। फलतः नगर की जनसंख्या उत्तरोत्तर वृद्धिमान गति पर है। अतः आवासों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। स्वभाविक है जब जनसंख्या तथा आवासों की संख्या में वृद्धि होगी तो गृहत्याज्य के संकलन एवं निस्तारण की समस्या भी बढ़ेगी। प्रस्तुत आलेख वारणसी नगर की इसी समस्या को उजागर करने का एक प्रयास रहा है।

8. "प्राचीन भारत में न्याय एवं दण्ड व्यवस्था में भेदभाव"—डॉ० शिवचन्द्र सिंह रावत, असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर, चमोली (उत्तराखण्ड), राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि, राजकीय विधि महाविद्यालय, गोपेश्वर, चमोली (उत्तराखण्ड)

भारतीय समाज में वर्ण-भेद प्राचीन काल से ही प्रचलित रहा है, जिस कारण समाज में आपसी भेदभाव के कारण एकरूपता व समरसता का अभाव रहा है। वर्ण-भेद ने जहाँ समाज के एक वर्ग को विशेषाधिकार युक्त व संपन्न बना दिया, वहीं दूसरी ओर निम्न वर्ग की स्थिति हर प्रकार से दयनीय बनी रही। समाज में यह भेदभाव विभिन्न रूपों में देखने को मिलता है, जैसे-खान-पान, रीति-रिवाज, विवाह आदि, परन्तु यह भेदभाव यहीं तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसके प्रभाव से न्याय व्यवस्था भी ग्रसित रही है। न्याय शब्द का अर्थ ही है—समानता या बराबरी, परन्तु प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था किसी भी दृष्टि से इस शब्द के अर्थ को चरितार्थ नहीं करती है। प्रस्तुत आलेख के अन्तर्गत इसी तरह प्राचीन भारतीय न्याय एवं दण्ड व्यवस्था में प्रचलित रहे भेदभावपूर्ण तत्वों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, जो कि एक विसंगति के रूप में आज भी न्याय व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। अंतर सिर्फ यह है कि प्राचीन न्याय एवं दण्ड व्यवस्था में भेदभाव का आधार वर्ण व्यवस्था था, जबकि आधुनिक युग में इस विसंगति का कारण अमीरी और गरीबी हो गया है।

9. "धर्मान्तरण और दलित"—डॉ० भारती सागर, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र, आर०सी०ए० कन्या महाविद्यालय मथुरा, (उ.प्र.)

जब से धर्म का जन्म हुआ तभी से धर्मान्तरण भी होता आ रहा है। यद्यपि धर्मान्तरण व धर्म का संबंध व्यक्तिगत आस्था से है तथापि यह सामाजिक सांस्कृतिक यहाँ तक कि राजनीति को भी प्रभावित करता भारतीय समाज इस प्रघटना से अछूता नहीं है। अतीत में झाँकें तो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारतीय जनता ने विविध परिस्थितियों व कारणों के प्रभाव में आकर धर्मान्तरण किया और साक्ष्य इनके द्वारा जबरन धर्मान्तरण की भी पुष्टि करते हैं। प्रस्तुत आलेख में भारतीय सामाजिक संरचना में कभी अस्पृश्य या अछूत के रूप में पहचाने जाने वाले दलितों के धर्मांतरण संबंधी आन्दोलनों और अनुभवों पर विचार किया गया है। तथ्य स्पष्ट करते हैं कि दलितों का धर्मान्तरण केवल आस्था परिवर्तन नहीं वरन् हिन्दू धर्म की सामाजिक व्यवस्था से हताश होकर दूसरे धर्म का इस आशा के साथ अंगीकरण है कि यहाँ उन्हें सम्मानजनक स्थिति व समानता के धरातल पर रहकर स्वउत्थान का मार्ग प्राप्त हो जाये। अछूतों का धर्मान्तरण आस्था परिवर्तन से इतना नहीं जुड़ा जितना कि अपनी सामाजिक प्रस्थिति में परिवर्तन से जुड़ा है।

10. "जनजातीय महिला विकास एवं भूमण्डलीकरण : एक समाजशास्त्रीय संदर्भ"—डॉ. कान्ता मीणा, याख्याता समाजशास्त्र, कनोरिया महिला, पी.जी. कालेज, जयपुर (राज.)

निरन्तर विकास किसी भी समाज के अस्तित्व हेतु एक आधारभूत आवश्यकता है जो कि सामाजिक इकाईयों के बीच स्पर्धा को जन्म देकर पारम्परिक समाज को जटिल समाज की ओर ले जाता है। कुछ समाजों में विकास की गति अति मन्द होती है और कुछ में अत्यधिक तीव्र। जनजातीय समाज मन्द गति से विकसित समाजों का ही एक स्वरूप है। प्रस्तुत आलेख के अंतर्गत भूमण्डलीकरण के वर्तमान दौर में जनजातीय महिला विकास की दशा और दिशा को प्रकाशित करने का एक प्रयास किया गया है।

11. "अम्बेडकर और बौद्ध धर्म"—डा. नागेश्वर प्रसाद, प्राचार्य, गन्ना उत्पादक पी.जी. कालेज, बहेड़ी, बरेली (उ.प्र.)

डॉ. अम्बेडकर में छात्रावस्था से ही बौद्ध धर्म के प्रति अभिरूचि पैदा हो गई थी। 1935 में उन्होंने हिन्दू धर्म को त्याग देने की इच्छा प्रकट कर दी थी। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली। इन दो दशकों के अंतराल में उन्होंने प्रमुख धर्मों की तुलनात्मक अन्तर्दृष्टि के पश्चात बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। उन्होंने बौद्ध धर्म द्वारा प्रसारित समानता, स्वतंत्रता तथा प्रेम की भावना का अवतसांत किया। इसी से उन्हें भारतीय समाज की सामाजिक कुरीतियों विशेषतः जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा मिली। बौद्ध धर्म का अम्बेडकर के चिंतन एवं कार्यों पर व्यापक प्रभाव परिलक्षित होता है प्रस्तुत आलेख के अंतर्गत इसी तथ्य को उजागर करने का प्रयास किया गया है।

12. "विवाह की आवश्यकता एवं आधुनिक युवतियाँ"—डॉ० सुषमा नयाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, एस०एम०जे०एन० (पी०जी०) कॉलेज, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

विवाह की आवश्यकता सामाजिक नियंत्रण के लिए अनिवार्य मानी जाती है यह मान्यता वैज्ञानिक के साथ सामाजिक भी है इसीलिए यह एक सार्वभौमिक संस्था के रूप में स्थापित है। यह यौनिक व्यवहार की सभ्य प्रक्रिया के लिए ही नहीं वरन बदलते समाज में सुलभ श्रम विभाजन एवं आर्थिक सहयोगात्मकता को भी विकसित करती है। वर्तमान युवा एवं भावी परिवारों की मुखिया इस पर क्या दृष्टिकोण रखती हैं इसके लिए प्राथमिक तथ्यों के माध्यम से यह अध्ययन प्रस्तुत है।

13. "घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 (रामपुर जनपद के विशेष संदर्भ में)"—प्रीति सक्सेना, शोध अध्ययत्री, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर (उ.प्र.), डॉ. अनीता देवी अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर (उ.प्र.)

पति एवं परिवार के सदस्यों द्वारा किये जाने वाले असमानतापूर्ण एवं हीनतापूर्ण व्यवहार, शोषण, अत्याचार तथा सामाजिक कुरीतियों के अंतर्गत किए जाने वाले उत्पीड़न एवं हिंसा को रोकने के लिए भारत सरकार ने महिला संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया है। यह अधिनियम कितना सफल हो पा रहा है इसकी सफलता में क्या बाधाएं अथवा सम्भावनाएं आ रही हैं, कितनी महिलाओं को इस अधिनियम की जानकारी एवं कितनी इससे लाभान्वित हो रही हैं, इन सब तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने की दिशा में एक प्रयास है प्रस्तुत अध्ययन।

14. "कृषक समाज में महिलाओं की भूमिका: एक अध्ययन"—शोभा राम डेहरिया, सहायक प्राध्यापक, समाज कार्य अध्ययनशाला, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर, (छत्तीसगढ़)

विश्व के लगभग समस्त समाजों में सामाजिक विकास की प्रत्येक अवस्था में तथा अर्थव्यवस्था के सभी स्वरूपों विशेषतः कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान अतिशय महत्वपूर्ण रहा है। वास्तव में महिलाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इसे स्त्रियों का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि कृषि से संबंधित प्रत्येक कार्य में महिलाएं पुरुषों के समान ही, कई बार अधिक सक्रिय होने के बावजूद कृषि को पुरुष प्रधान व्यवसाय कहा जाता है, उनकी गणना कृषित श्रमिक शक्ति के अंतर्गत नहीं की जाती है, उन्हें परिवार के कमाऊ सदस्य की संज्ञा नहीं दी जाती तथा परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं की संपूर्ति में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करने के बाद भी उन्हें पुरुष के समकक्ष स्थान प्राप्त नहीं होता। छत्तीसगढ़ राज्य के जनपद बस्तर के ग्राम चिहलागुड़ा (कुम्हली) पर आधारित प्रस्तुत अध्ययन सांप्रत भातर में कृषक समाज में महिलाओं की भूमिका को उजागर करने का एक प्रयास रहा है।

15. "रामपुर जिले में पत्तीवर्क: इतिहास और विकास"—श्रीमती शहला शाही, शोध अध्येत्री, समाजशास्त्र, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर (उ.प्र.), डॉ. प्रभा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर (उ.प्र.)

भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ पूँजी का अभाव और बेरोज़गारी का साम्राज्य है, कुटीर एवं लघु उद्योग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी पहलुओं से देश के औद्योगिक विकास की आधारशिला हैं। लघु उद्योगों के माध्यम से कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल सभी प्रकार के श्रमिकों को रोज़गार मिलता है। प्रस्तुत आलेख उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद रामपुर के लघु उद्योग 'पत्ती वर्क', जो आज प्रदेश अथवा देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी पसंद किया जाता है, के ऐतिहासिक विकास को प्रकाशित करने का एक प्रयास रहा है।

16. "विलुप्त होते खलिहान"—डॉ० राजेश कुमार पाल, प्रवक्ता समाजशास्त्र, गोस्वामी तुलसीदास राजकीय महाविद्यालय, कर्वी चित्रकूट (उ०प्र०)

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खलिहानों की एक समृद्ध परम्परा रही है। खलिहान सिर्फ फसलों के संकलन स्थल ही न थे वरन् सामुदायिकता, सामूहिकता, आत्मनिर्भरता के अंग भी थे। खलिहान आर्थिक केन्द्र बिन्दु के साथ-साथ अन्तरजातीय सम्बन्धों के प्रतीक भी थे। प्रस्तुत अध्ययन में खलिहानों के विलुप्त होने के कारणों एवं ग्रामीण अंचलों में उसकी उपयोगिता को दर्शाने का प्रयास किया गया है।

17. "नगरीय शासन के अन्तर्गत महानगरपालिकाओं की भूमिका"—डॉ. निधि रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र, डी.ए.वी. कालेज, बुढाना, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.)

प्रस्तुत शोध पत्र जनपद मेरठ में नगर निगम चुनाव के अन्तर्गत महानगर पालिकाओं की भूमिका के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। यह अध्ययन जनता पर राजनीतिक परिपेक्ष्य में सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव दोनों के सूचनादाताओं लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए किये गये प्रयास एवं उनके प्रभाव का वर्णन करता है। प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक स्रोतों पर आधारित है जिसमें साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से सामग्री एकत्रित की गई है।

18. "उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की शिक्षण अभिक्षमता तथा कार्य सन्तुष्टि का अध्ययन"—गजपाल रामराज, शोधार्थी, शिक्षा विभाग, हे०न०ब०ग० केन्द्रीय वि०वि० श्रीनगर-गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

यह सार्वभौमिक सत्य है कि किसी भी देश, काल अथवा स्थान में समाज व शिक्षा के अभाव में मानव मात्र पशुवत, ज्ञान हीन एवं अस्तित्वहीन है। शिक्षा प्रदान करने वाला अर्थात् शिक्षक ही बालक की जन्मजात पाशिवक प्रवृत्ति का दमन करके उसे मानव बनाता है जिसके लिए शिक्षक में शिक्षण अभिक्षमता होनी आवश्यक है। प्रस्तुत आलेख उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की शिक्षण अभिक्षमता तथा कार्य संतुष्टि के अध्ययन पर आधारित है।

19. "संयुक्त परिवारों का बदलता स्वरूप — एक समाजशास्त्रीय अध्ययन"—कवलजीत कौर, शोध अध्येत्री, समाजशास्त्र विभाग, एम.बी. (पी.जी.) कॉलेज, हल्द्वानी, नैनीताल, (उत्तराखण्ड)

परिवार ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो बच्चे को समाज के नियमों से परिचित कराती है, उसमें मानवीय गुणों का विकास करती है तथा एक जैवकीय प्राणी को सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित करती है। प्राचीन काल से ही भारत में जिस परिवार व्यवस्था को विकसित किया गया, उसे हम संयुक्त परिवार के नाम से जानते हैं। परिवर्तन के इस युग में परिवार के परम्परागत स्वरूप में लगातार परिवर्तन हो रहा है। इस लघु शोध के अन्तर्गत संयुक्त परिवारों के बदलते स्वरूप के कारणों को जानने का प्रयास किया गया है।

20. "बिहार के नालन्दा जनपद में प्रारंभिक शिक्षा के बदलते आयाम : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन"—गोपाल कुमार, बिहार

स्वतंत्रोपरांत बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा में वृद्धि हुई है। शिक्षकों की संख्या तथा विद्यार्थियों की संख्या में भी उल्लेखनीय अभिवृद्धि हुई है। बिहार राज्य सहित संपूर्ण देश को शिक्षित एवं सामर्थ्यवान बनाने के लिए हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। सरकारी विद्यालयों को सुसज्जित अर्थात् सुविधायुक्त बनाना होगा। साक्षरता में सफलता तभी प्राप्त होगी जब शिक्षा शिक्षा लोगों की वास्तविक जरूरत बन जाये, लोग स्वयं साक्षरता की मांग करें अर्थात् व्यक्ति शिक्षा को रोटी जितना महत्वपूर्ण समझे— समाज में ऐसी जागृति फैलानी होगी। बस आवश्यकता है दृढ़ राजनीतिक संकल्प, प्रशासनिक सुव्यवस्था, ईमानदारी एवं कर्मठता से कदम बढ़ाने की। बिहार राज्य इस दिशा में तीव्र गति से अग्रसर है। प्रस्तुत आलेख बिहार में इस दिशा में किये गये व्यापक शासकीय प्रयासों को प्रकाशित करने के प्रयास पर आधारित है।

21. "बाल श्रम : समस्या और सरकारी प्रयास"—अभिलाषा गौड़ सारस्वत, प्रवक्ता, गृह-विज्ञान, साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय, बरेली (उ.प्र.)

बाल श्रम की समस्या यद्यपि विश्व के समस्त विकसित एवं विकासशील देशों में परिव्याप्त है किन्तु भारत में यह बीमारी अपने गंभीरतम रूप में एक कलंक की तरह विद्यमान है। यह कहा जाता है कि जिस देश में गरीबी, बेकारी, भुखमरी एवं पिछड़ापन जितना अधिक होगा वहां बालश्रम एवं उसका शोषण उतना ही अधिक होगा। ये सामाजिक बीमारियां भारत में अपने चरम रूप में विद्यमान हैं इसलिए बाल श्रम की समस्या की विकरालता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। प्रस्तुत लेख के अंतर्गत बाल श्रम की समस्या की गंभीरता इसके कारण तथा इस समस्या के उन्मूलन हेतु कानूनी प्रावधानों तथा शासकीय योजनाओं की विस्तृत व्याख्या की गई है।

22. "गढ़वाल हिमालय के भेड़पालक समुदाय का आर्थिक अध्ययन"—डॉ० सोना पैन्थूली उनियाल, प्रवक्ता संविदा, मानवविज्ञान विभाग, बाल गंगा महाविद्यालय सेन्दुल केमर, टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

उत्तराखण्ड के टिहरी जनपद के सीमान्त विकास खण्ड भिलंगना का गंगी गांव, जो प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र रहा है का भेड़पालक समुदाय जो संसाधन, शक्ति एवं सम्मान से वंचित है, अपनी असीमित आवश्यकताओं को सीमितता में संजोने, विकट भौगोलिक परिस्थितियों में जीवन यापन करने, छः-छः मास के प्रवासी, यात्रायुक्त जीवन पद्धति में अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए विवश है। प्रस्तुत अध्ययन इसी भेड़पालक समुदाय के जीवन के आर्थिक पक्ष अर्थात् उनकी अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करने के प्रयास पर आधारित है।

23. "उत्तराखण्ड के वाद्य यन्त्रों का सामाजिक एवं आध्यात्मिक महत्व"—कु० लीला कन्याल, शोध अध्येत्री, दर्शनशास्त्र विभाग, हे०न०ब० गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

उत्तराखण्ड देवभूमि मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र प्राचीनकाल से ही यह चिन्तकों, देवी-देवताओं की निवास स्थली, ऋषि मुनियों की तपोभूमि के आकर्षण से अनेकों राजा-महाराजाओं ने अपने गढ़ यहाँ स्थापित किये। इसी दिव्यभूमि में हिमपति भगवान शंकर ने सर्वप्रथम सृष्टि के मनोरंजन के लिए ढोल और डमरू को धारण किया। भगवान श्रीकृष्ण द्वापर युग में युग पुरुष रहे तो बाँसुरी अर्थात् मुरली इनका प्रिय वाद्य रहा है। जब रामचन्द्र जी ने धनुष तोड़ा तो दुंदुभी ढोल एवं नगाड़े इत्यादि बजने लगे। इस प्रकार से पौराणिक काल से ही इन वाद्यों का प्रचलन होने के कारण ही हम अपने कुछ लोक वाद्यों को पौराणिक वाद्य भी कहते हैं। उत्तराखण्ड के वाद्यों में चार वाद्य निहित हैं— चर्म, सुषिर, तार एवं धातु। इन्हीं वाद्य के माध्यम से ही हमारे

धार्मिक सामाजिक एवं मांगलिक कार्य सम्पन्न होते हैं। प्रस्तुत लेख में उत्तराखण्ड के वाद्य यन्त्रों के सामाजिक एवं आध्यात्मिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

24. "बुन्देलखण्ड की प्राचीन सरोवर निर्माण परम्परा"—आलोक कुमार पाण्डेय , शोध अध्येता, इतिहास, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, सतना (म0प्र0)

यह बात जग जाहिर है कि बुन्देलखण्ड एक जमाने में अपनी जल समृद्धि परम्परा के लिए जग प्रसिद्ध रहा है। यहाँ के जल-स्रोत जैसे नदी, सरोवर, बावड़ियों तथा पातालतोड़ कुएं सभी ने इस क्षेत्र को अपने जल से रससिक्त किया है। प्राचीन विशाल सरोवरों से युक्त यह क्षेत्र जल संरक्षण के क्षेत्र में प्रमुख रहा है। किन्तु विगत कुछ वर्षों में जल की बढ़ती मांग, जल स्रोतों का अकुशल, अवैज्ञानिक व अति दोहन आदि कारणों से इस उपयोगी संसाधन का समूल अस्तित्व संकट में पड़ गया है। प्रस्तुत आलेख बुन्देलखण्ड के परिप्रेक्ष्य में प्राचीन सरोवर निर्माण परम्परा की वर्तमान में दशा और दिशा का तथ्यपरक एवं तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

25. "सरकारी और निजी प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित अधिगम संबंधी कठिनाइयों का तुलनात्मक अध्ययन"—ओम प्रकाश जोशी, असिस्टेंट प्रोफेसर बी0एड0 विभाग, पाल कॉलेज ऑफ़ टैक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट, हल्द्वानी, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

वर्तमान शिक्षा प्रणाली पुनर्रचना के दौर में है उसका उद्देश्य मात्र कक्षा उन्नति रह गया है, कक्षा की शैक्षिक सामग्री को आत्मसात् करना नहीं है। यह तथ्य प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से और देखने को मिलता है। कक्षा में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पाठ्यक्रम में गणित के अलावा अन्य विषयों में उनकी पकड़ अच्छी होती है। लेकिन गणित में उनकी उपलब्धि निम्न स्तर की होती है उन्हें गणित के अधिगम में कठिनाई होती है। इस कारण इन बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोधपत्र में शोधकर्ता द्वारा सरकारी व निजी प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की गणित अधिगम संबंधी कठिनाइयों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

26. "प्लेटो के शिक्षा सिद्धान्त की वर्तमान में उपयोगिता"—दलीप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, गर्ग डिग्री कालेज, लक्सर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

प्लेटो की मान्यता थी कि किसी भी श्रेष्ठ राजनीतिक जीवन के निर्माण के लिए श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली का होना अत्यावश्यक है। प्लेटो अपनी शिक्षा योजना के माध्यम से एक ओर तो पूर्णतः सामाजिक नागरिकों का विकास करना चाहता था तो दूसरी ओर वह ऐसे मानव का निर्माण करना चाहता था जो सर्वदाता होने के नाते आदर्श राज्य के संचालन का सर्वोच्च अधिकारी बन सके। इसीलिए मैक्सी ने लिखा है कि प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से आधुनिक लगती है अर्थात् वह सांप्रतिक समाज के लिए भी अतिशय उपयोगी है। प्रस्तुत आलेख के अंतर्गत इसी तथ्य को उजागर करने का प्रयास किया गया है।

27. "अनुसूचित जातियों में सामाजिक गतिशीलता"—मनोज कुमार, शोध अध्येता, समाजशास्त्र, कुमाऊं विश्वविद्यालय कुमाऊं, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

स्वतंत्रोपरांत भारत में अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं उन्नति हेतु कार्यान्वित अनेकानेक शासकीय सुविधाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों के फलस्वरूप अनुसूचित जातियों की समाजार्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में अनेक प्रगतिकारी परिवर्तन घटित हो रहे हैं तथा उनकी गतिशीलता में अभिवृद्धि हो रही है। प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत अनुसूचित जातियों की सामाजिक गतिशीलता को जानने का प्रयास किया गया है।

28. "दलित समाज और शिक्षा का ऐतिहासिक अध्ययन"—डॉ. भावना खरे, सहायक प्राध्यापक, रावतपुरा शासकीय महाविद्यालय, बनखेड़ी होशंगाबाद (म.प्र.)

पूर्व स्वतंत्रताकालीन भारत में दलितों को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारों से पूर्णतः वंचित रखा गया था। स्वतंत्रोपरांत भारत में शैक्षिक क्षेत्र में, उनके अभ्युत्थान हेतु अनेकानेक सुविधाओं, कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अनवरत प्रयास किये जाते रहे हैं जिनके फलस्वरूप उनकी शैक्षिक स्थिति में अवश्यमेव परिवर्तन हो रहा है। प्रस्तुत आलेख शैक्षिक क्षेत्र में दलितों की इसी परिवर्ती स्थिति को प्रकाशित करने का एक प्रयास है।